Prabhurashtra

Global standard warning label will boost India's packaged food export

ग्लोबल स्टैंडर्ड वॉर्निंग लेबल भारत के पैकेज़्ड फूड एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा

कोलकाता। अल्ट्रा-प्रोसेस्ड पैकेज़्ड फूड का इस्तेमाल अप्रत्याशित रूप से बढ़ता जा रहा है, इसलिए भारत में विज्ञान आधारित फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग (एफओपीएल) को प्राथमिकता दी जा रही है। इस विषय में आयोजित एक कार्यक्रम में, उद्योग के मुख्य प्रतिनिधियों और फूड निर्माताओं ने बताया कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ विधि एफओपीएल से पैकेज़्ड फूड उत्पादों, खासकर जो फूड एमएसएमई यूनिटों द्वारा बनाया जाता है, उसे दुनिया के बाजारों में एक्सपोर्ट किए जाने को काफी बढ़ावा मिलेगा। भारत में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड एवं बेवरेज के लिए वृद्धि की दर सर्वाधिक है। यह फूड सामग्री अल्ट्रा-प्रोसेस्ड होने के अलावा इसमें काफी ज्यादा मात्रा में एडेड शुगर, साल्ट एवं एडिटिव्स होते हैं। 2006 से 2019 के बीच यूरोमॉनिटर सेल्स डेटा के मुताबिक पैकेज्ड जंक फूड एवं सॉफ्ट ड्रिंक्स का रिटेल मूल्य भारत में 13 सालों में 42 गुना बढ़ गया। फूड प्रोसेसिंग उद्योग, जिसे भारत सरकार रोजगार निर्माण के लिए मुख्य सेक्टर मानती है, मौजूदा समय में 200 बिलियन डॉलर का है, जो बढ़कर 500 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। भारत के 32 प्रतिशत फूड बाजार में 'प्रोसेसिंग उद्योग' का वर्चस्व है, इसलिए स्वादिष्ट एवं लोकप्रिय देसी स्नैक और कन्फेक्शनरी बनाने वाला विशाल एमएसएमई सेक्टर इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एमएसएमई सेक्टर की इस क्षमता को समझते हुए सरकार प्रोसेसिंग उद्योग के लिए फूड पार्क को बढ़ावा दे रही है और प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए तत्पर है। 10,900 करोड़ रु. की वित्तीय परिव्यय लागत से बनी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ (पीएलआईएस-एफपीआई) भारत में विश्व स्तर की फूड मैनुफैक्चरिंग कंपनियों को प्रोत्साहित करती है और भारतीय फूड ब्रांड्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सपोर्ट करने में सहयोग करती है। भारतीय फूड को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकने वाले फूड के समतुल्य बनाने के लिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ विधि, एफओपीएल को अपनाए जाने की जरूरत के बारे में एसोचैम, उत्तर प्रदेश के वाईस प्रेसिडेंट, श्री मनीष अग्रवाल ने कहा, ''भारतीय फूड एमएसएमई के लिए एक बड़ा लक्ष्य वैश्विक एक्सपोर्ट के अनुरूप पारंपरिक फूड के सेहतमंद रूपों को अपनाना है, जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके। फूड लेबलिंग के वैश्विक स्तरों के साथ सामंजस्य बिठाकर और नमक, चीनी एवं फैट की मात्रा निर्धारित करके भारत को इस अपार क्षमता का काफी लाभ मिल सकता है, जिससे भारत के पारंपरिक स्नैक के लिए एक बहुत विशाल बाजार के द्वार खुल जाएंगे।''